MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Government of Maharashtra have demanded a quota of 15,500 MT of edible oil per month in December, 1991.

(b) A quantity of 12000 MT imported Palmolein was allocated to Maharashtra during oil year 1991-92 (Nov. to Oct.). In addition, Maharashtra Government imported a quantity of 7807 MTs of Palmolein directly in 1992.

(c) The allocation of imported edible oil is supplemental in nature. It is allocated to States/UTs keeping in view the stock position of imported palmolien with State Trading Corpn. indigenous availability of edible oils and prices thereof, demand of all States and UTs etc.

Closure of fair price shops

3273. CHOWDHARY HARI SINGH : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DITRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of fair price shops in district Bulandshahar, Uttar Pradesh have been closed illegally during the year 1992; and

(b) the number of such fair price shops closed in the above district upto 4th March. 1993 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) The information is being obtained from Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House.

राशन विक्रेताओं में आक्रोश

3274. **श्री सोम पाल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में "खाद्यान्न आपूर्ति में हेराफेरी से राशन विक्रेता नाराज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राशन विक्रेताओं को दिए जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी की मात्रा में कमी करने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेवार हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में दुकानदारों को ये वस्तुएं यथेष्ठ मात्रा में मिलें ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, हर मास 10 से 12 लाख बोरियों की आपूर्ति कर रहा है। उचित दर दुकानों को पहुंचने वाली कुछ बोरियों में कम वजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) उचित दर दुकानदारों को, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जा कर खाद्य वस्तुओं की क्वालिटी तथा वजन की जांच करने का अधिकार है ।

(2) बोरियां दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तोली जाती हैं, जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर दुकानों के दरवाजों तक खाद्य वस्तुओं की ढुलाई करता है ।

(3) बोरियों में कम वजन होने तथा खराब क्वालिटी की शिकायतें 72 घंटों के भीतर मंडल कार्यालयों में